दिल्ली में लूटने हेतु बनी बिजली कंपनियां

क्या कभी अपके साथ ऐसा हुआ है कि आपका बिजली का बिल अनाप शनाप आया हो और आपको बिजली बोर्ड ने कहा हो कि कोई बात नहीं अभी हम आपकी बिजली नहीं काट रहे, पहले हम आपका बिल ठीक करेंगे और फ़िर आपसे उसे भरने को कहेंगे वो भी बिना किसी जुर्माने के? नहीं ना। यहां तो तीन का चाहे, गलती से, तीस हज़ार रुपये बिल आ जाये, पहले उसे भरवाया जायेगा और फ़िर उसे ठीक करने की बात सुनी जायेगी। लेकिन दिल्ली में ठीक उलटा हो रहा है, आपके साथ यही दादागिरी करने वाली बिजली वितरण कम्पनियां ('डिस्कॉम्ज़')अपनी बारी आने पर उलटा कह रही हैं। उन्होंने देश के सर्वोच्च न्यायालय से गुहार लगायी है कि बिल ना भरने के एवज में, उनको बिजली सप्लाई करने वाली कम्पनी एन. टी. पी.सी. को सप्लाई काटने से रोका जाये। यानि उपभोक्ता आपका अनाप शनाप बिल अदा ना करे तो आप उसकी बिजली काट दो लेकिन आप अपना जायज बिल भी ना भरो तो आपकी बिजली नहीं कटनी चाहिये। लेकिन हमारे सर्वोच्च न्यायालय की, इन बिजली कम्पनियों के प्रति रहमदिली देखिये कि उन्होंने सरकारी कम्पनी एन.टी.पी.सी.को 26 मार्च यानि डेढ़ महिने तक इन दिल्ली की 'डिस्कॉम्ज़' की बिजली काटने से रोक दिया क्योंकि वे बेचारे अम्बानी जैसे 'गरीब' की कंपनियां जो है। ये वही अम्बानी हैं जिन्होंने दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो खा पी कर वापिस सरकार के गले बांध दी, जिसने के.जी.डी-6 क्षेत्र से गैस तब तक नहीं पूरी निकालना शुरू किया जब तक उसके चौगुने दाम सरकार से नहीं ले लिये, जिसने मुंबई में अभी तक भी, दो साल की लेटलतीफी के बाद भी, मेट्रो पूरी नहीं की है।

दक्षिणी दिल्ली को बिजली वितरण करने वाली कम्पनी बी.एस.ई.एस राजधानी के उदाहरण से हम इस मामले को समझ सकते हैं। इस कम्पनी नें दिल्ली सरकार से उपभेक्ताओं को दी जाने वाली सब्सिडी के 166.4 करोड़ रुपये लेने हैं। उसे दक्षिण दिल्ली की म्युनिसिपल कारपोरेशन से 118 करोड़ रुपये लेने हैं। हालांकि इस रकम पर कोर्ट में मुकदमा चल रहा है क्योंकि यह स्ट्रीट लाईटों का बिल है जो घरेलू दरों से चार्ज किया जाना चाहिए था जबकि कंपनी ने इसको कमर्शियल दरों से चार्ज किया है। म्युनिसिपल्टी के अनुसार यह बिल 90 करोड़ के लगभग है। उधर हर बिल पर 5 पैसे प्रति यूनिट म्युनिसिपल टैक्स, उपभोक्ताओं से लिया जाता है। इस मद में बिजली कंपनी को 51 करोड़ रुपया म्युनिसिपिल्टी को देने हैं। यानि कि उतरम पातरा करके 43 करोड़ रुपये दक्षिण दिल्ली म्युनिसिपल्टी को बी.एस.ई.एस. राजधानी को देने हैं।

उधर देनदारी देखें तो बिजली कंपनी को 590 करोड़ रुपये एन.टी.पी.सी. आदि को और 2846 करोड़ रुपये दिल्ली सरकार के बिजली घरों को देने हैं। यानि कि बिजली कंपनी को कुल 3436 करोड़ रुपये देने हैं जबकि उसे सिर्फ 210 करोड़ रुपये लेने हैं। यानि कि '3226' करोड़ रुपये नेट कंपनी ने देने हैं। यह सभी आंकड़े शनिवार 8 फरवरी 2014 के टाईम्स ऑफ़ इंडिया अखबार से लिये गये हैं। यहां यह जान लेना भी उचित होगा कि एन.टी.पी.सी. ने जो इस बिजली कंपनी (बी.एस.ई. एस राजधानी) को बिजली सप्लाई करने का 590 करोड़ रुपये का बिल दिया है उस पर किसी तरह का विवाद नहीं है। यानि कि 'डिस्काम' मान रही है कि यह बिल बिलकुल ठीक है और उसे इतने रुपये एन.टी.पी.सी को उससे खरीदी बिजली के देने हैं।

लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का न्याय देखिये कि कोई गलती न होने के बावजूद एन.टी.पी.सी. को तो 26 मार्च तक बिजली काटने से रोक दिया जबकि 'डिस्कॉम्स' को सिर्फ़ 50 करोड़ रुपये वह भी दो हफ़्ते में अदा करने को कहा गया है। क्या यही आदेश तब भी पारित किये जाते जब एन.टी.पी.सी. ने बिजली कंपनी से पैसे लेने नहीं बल्कि देने होते। और इतनी मोटी रकम पर डेढ़ महीने का ब्याज कौन देगा? इसी बीच 326 करोड़ रुपये का एक बिल एन.टी.पी.सी. ने और दिया है उसका क्या होगा? और इस डेढ़ महीने में जो बिजली का बिल आयेगा उसका क्या होगा?

ध्यान देने की बात ये है कि पैसे का रोना सिर्फ़ अम्बानी की दोनों कम्पनियां ही रो रही हैं। दिल्ली में बिजली सप्लाई करने वाली तीसरी डिस्कॉम टाटा की है। उसे किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है जबकि उसका क्षेत्र सबसे ज़्यादा घाटा देने वाला था। लेकिन क्योंकि अम्बानियों ने तो अपना साम्राज्य ही नेताओं और अफ़सरों की मिलीभगत से, जनता के पैसे को लूटकर खड़ा किया है इसलिये उन्हें कहीं भी मेहनत से और सिर्फ जायज कमाई ही मिले तो उन्हें बड़ी तकलीफ़ होती है। और वो तुरन्त सरकार की, और वास्तव में इस देश की जनता की बाहें मरोड़ना शुरू कर देते हैं। यही उन्होंने ऐयरपोर्ट मेट्रो में किया, यही गैस निकालने में किया और यही अब यहां बिजली के क्षेत्र में शुरू कर दिया। दस-दस घण्टे के बिजलीकट का हौवा दिखाकर लोग़ों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। उनके इस ब्लैकमेल को रोकने में सुप्रीम कोर्ट भी नाकाम रहा है और 'टाईम्स ऑफ़ ईडिया' जैसे अखवार तो बल्कि इसमें उनके औज़ार की तरह काम कर रहे हैं।

इस खबर को इस अखबार ने यह कह कर छापा कि सरकार और इन कंपनियों के झगड़े में जनता पिसेगी, बिजली कटने से परेशान होगी जिसने अपना पूरा बिल भरा है। यानि कि उसने भी जनता को भावनात्मक ब्लैकमेल करने की कोशिश की है कि उसकी बिजली नहीं कटनी चाहिए और इसके लिये बिजली कम्पनी को राहत दी जाये। इस तरह इन ठगों की लूट जारी रखने के लिये टाईम्स ऑफ़ इंडिया ने ज़मीन तैयार कर दी और जरूरी आदेश सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिये। अब ये दिल्ली की जनता और उसकी रहनुमा 'आप' पार्टी को तय करना है कि वह इन कानूनों के जंजाल में फंसेगी या इन जनता की बांह मरोड़ने वालों की खुद की बाह ही उखाड़ फेंकेगी।

-अजातशत्रु

सांसद भड़ाना केवल लफ़्फाजी के लिये

....बन गए जनाब हीरो
कामकाज में बिल्कुल ज़ीरो

जहां एक ओर मल्लिकार्जुन खरगे व ऑस्कर फर्नांडिस जैसे कर्नाटक के सांसद मात्र डेढ लाख ई एस आई सी में शामिल श्रमिकों के लिये 500 बेड का अस्पताल व मेडिकल कॉलेज ले गये, वहां फ़रीदाबाद के सांसद अवतार सिंह भड़ाना को तो शायद पता भी नहीं कि उसके क्षेत्र के 5 लाख श्रमिक परिवार अपने वेतन से पैसा कटवा कर भी चिकित्सा सुविधाओं के लिये किस तरह भटकते फ़िर रहे हैं। उन्होंने कभी यह जानने की जरूरत महसूस नहीं की कि उनके क्षेत्र में चलने वाले ई एस आई सी अस्पतालों व डिस्पेंसरियों में आखिर मज़दूरों के साथ हो क्या रहा है। उन्होंने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि एन एच-3 स्थित अस्पताल के लिये पैरा मेडिकल स्टाफ़ की भर्ती हेतु आवेदन प्राप्त करने के बावजूद उसे स्थगित क्यों कर दिया गया?

हां, भडाना से लफ़्फाजी जितनी मरजी करा लो। वाहियातपने की भाषणबाज़ी करने में इनका कोई सानी नहीं। मुख्यमंत्री व देश का गृह मंत्री बनने के ख्वाब देखने वाले इन महोदय को कभी संसद में अपने क्षेत्र की कोई समस्या उठाने की न तो समझ रही है और न ही कभी आवश्यकता समझी। हां स्थानीय अफ़सरों को धमका कर अपने अहम की सन्तुष्टि जरूर कर लेते हैं।

दरअसल पत्थर खदानों से बेतहाशा लूटे गये काले धन की बदौलत सांसद बने एक अनपढ, शिला समान व्यक्ति से और कोई उम्मीद भी क्या की जा सकती है। उसी काले धन की ताकत पर इस बार भी वे सांसद बनने की जुगत भिड़ा रहे हैं। अब देखना यह है कि जनता काठ की हांड़ी कितनी बार चढाती है? अब देखना है कि मतदाता शराब व पैसे के बदले अपना वोट बेचते हैं या काम के आधार पर वोट देते हैं।

लगता है केजरीवाल ने 'मज़दूर मोर्चा' पढ़ लिया

भ्रष्टाचार पर 'आप' का रोड रोलर चल पड़ा

फ़रीदाबाद (म.मो.) 'मज़दूर मोर्चा' के दिनांक 1-15 फरवरी अंक के मुख पृष्ठ पर 'लोकपाल नहीं, कार्यपाल चाहिये, केजरीवाल जी!' शीर्षक से लेख प्रकाशित हुआ था। उस लेख का एक विशेष भाग इस प्रकार है।

दरअसल दिल्ली सरकार के विजिलेंस विभाग को मजबूत कर इसे भ्रष्टाचार विरोधी दस्ते की बजाय भ्रष्टाचारनाशक रोडरोलर के रूप में बदला जा सकता है। यह पूर्णतया दिल्ली सरकार की पहल का मामला है। सरकार चाहे तो सैंकड़ों की संख्या में युवा अनुसंधानकर्ता (तफ़्तीशी) विजिलेंस विभाग में भर्ती कर सकती है। इन्हें कुछ महीनों का गहन प्रशिक्षण देकर भ्रष्टाचार के मामलों को पकड़ने में लगाया जा सकता है। इनके अधिकारक्षेत्र में दिल्ली पुलिस ही नहीं बल्कि राज्य व केन्द्र सरकार के तमाम अधिकारी/कर्मचारी आयेंगे जो दिल्ली में कार्यरत हैं। यही नहीं कार्यपालिका एवं विधायिका के अलावा न्यायपालिका का भ्रष्टाचार भी विजिलेंस विभाग द्वारा ही देखा जायेगा।

अपने विजिलेंस विभाग के लिये अधिकारियों की मांग लेकर अभी दिल्ली सरकार को केन्द्रीय गृह मन्त्रालय/दिल्ली पुलिस के पास जाना पड़ता है। वहां से आनेवाले प्रायः स्वयं भ्रष्ट होते हैं। साथ ही उनकी दिलचस्पी अपने सहयोगियों के विरुद्ध कार्यवाही में कम और उनकी मदद में ज़्यादा होती है। इस समस्या का हल दिल्ली सरकार अपना विजिलेंस बोर्ड बनाकर कर सकती है। इस बोर्ड में वह अपनी तबियत के ईमानदार व कार्यकुशल व्यक्तियों को लगाकर वांछित परिणामों को सुनिश्चित कर सकती है। बोर्ड की शक्तियों को परिभाषित करना राज्य सरकार के अपने हाथ में है। उनके जिम्मे विजिलेंस विभाग की निगरानी व मार्गदर्शन की जवाबदेही डाली जा सकती है। इसके लिये न विधानसभा की मुहर चाहिये और न केंद्र सरकार की स्वीकृति।

अगर भ्रष्टाचार मिटाना है केजरीवाल जी तो कार्यपालकों का रोडरोलर चलाना ही पड़ेगा। जितना जल्दी चलाना शुरू कर सकें उतनी 'आप' की विश्वसनीयता बढ़ेगी।

लगता है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेख समझ में आ गया। समझ में आते ही उन्होंने भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपना रोड रोलर चलाना शुरू कर दिया। जनलोकपाल बनेगा तब बनेगाया या नहीं बनेगा या बन भी गया तो कुछ कर पायेगा या नहीं, कुछ पता नहीं। लेकिन विजिलेंस रूपी रोड रोलर जो उनके पास है वह तमाम तरह के भ्रष्टाचार से निपटने के लिये चल पड़ा है।

इस रोड रोलर के पहले शिकार बने हैं रिलांयस इंडस्ट्रीज़ के मालिक मुकेश अम्बानी तथा उनके इशारों पर नाचने वाले मौजूदा व पूर्व पैट्रोलियम मन्त्री वीरप्पा मोइली और मुरली देवड़ा, इनको सहयोग देनेवाले तत्कालीन डी जी हाइड्रोकार्बन वी के सिब्बल तथा अन्य अधिकारी। इन सबके विरुद्ध दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने आपराधिक मुकदमा दर्ज करके कार्यवाही शुरू कर दी है। इन पर आरोप है कि इन्होंने मिलकर केजी बेसिन से निकलने वाली प्राकृतिक गैस का भाव जो पहले 2.34 डॉलर से बढाकर 4.2 डॉलर कर दिया गया था, उसे बढाकर 8.2 डॉलर प्रति यूनिट करने का षड़यन्त्र रचा है। षड़यन्त्र कामयाब होने पर मुकेश अम्बानी को 54500 करोड़ का अतिरिक्त लाभ प्रति वर्ष मिलेगा।

अब, क्योंकि केजरीवाल को अपनी शक्तियों का ज्ञान हो गया है, इसलिये बहुत जल्दी कई और बड़े मगरमच्छों पर शिकंजा कसा जा सकता है।

सूरजकुंड मेले का तमाशा

फ़रीदाबाद (म.मो.) 28वां अन्तर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प सूरजकुंड मेला हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी अपने पीछे कई विवाद छोड़ गया है और इन विवादों तथा बदइंतजामी के लिये हरियाणा टूरिज्म के बेशर्म अधिकारियों ने मेला शुरू होने से ठीक एक दिन पहले प्रेस वार्ता में पूरे मीडिया जगत के आगे अपनी नालायकियों पर पर्दा डालने के लिये खबरें न छापने के लिये अनुरोध किया था। जिस मीडिया का इस थके हुए मेले को अन्तर्राष्ट्रीय मेला बनाने में अहम रोल है। उसी मीडिया को ढंग से बैठाने का भी कोई इन्तजाम नहीं किया। जब मीडिया की सीटों पर इन चापलूस अधिकारियों ने बाहर के राज्यों से आए मेहमानों को बिठाकर और उनकी आवभगत तो शुरू की तो उन्हें दिल्ली से आए कुछ पत्रकारों का अच्छा-खासा विरोध झेलना पड़ गया। और जब वह पत्रकार मेले की इस कॉन्फ्रेंस को छोड़ कर जाने लगे तभी मेले के अधिकारियों ने उन मेहमानों से सीटों को खाली करवा कर पत्रकारों को बिठाया। और जब 11 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस 1 घंटे बाद शुरू हुई जिसका कारण यह था कि दिल्ली टूरिज़्म के एक वरिष्ठ अधिकारी ठीक समय पर नहीं पहुंच पाए ।

प्रेस कॉन्फेंस में बड़े-बड़े दावे करने वाले इन अधिकारियों की पोल तब खुली जब कवि सुरेन्द्र शर्मा ने अपनी चार लाईन पंक्ति की शुरूआत ही की थी कि हल्की बारिश पड़ गई और टूरिज़्म विभाग की तरफ़ से इस हल्की बारिश से निपटने के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए थे। जिस वजह से कवि सुरेन्द्र शर्मा को अपना कार्यक्रम बारिश के चलते जल्दी निपटाना पड़ा। इससे भी सबक न लेकर इन ऐश-परस्त अधिकारियों ने खुले मैदान में रात का फैशन शो का आयोजन कर डाला।

कुछ ही देर में यह फैशन शो लोग़ों के लिए लाफ़्टर शो बन कर रह गया। इस फैशन शो की शोभा हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव एस सी. चौधरी बढ़ा रहे थे। जब कुछ ही देर में खुले मैदान में बैठे वी.वी. आई.पी. अधिकारियों के लाडलों-लाडलियों को सर्दी के चलते दो-चार छींक आई तब टूरिज़्म विभाग की एक महिला अधिकारी ने अपनी चापलूसी की परम्परा को बढ़ाते हुए तुरन्त दो गैस हीटर लगवा दिये। जब इससे भी बात नहीं बनी तो वी.आई.पी. धीरे-धीरे जाने लगे और फैशन शो कम लॉफ़्टर शो को देखने वाले गायब से होने लगे।

तब इस महिला अधिकारी ने फैशन शो आयोजकों को कहकर मात्र एक घंटे में निपटा दिया। प्रेस-कॉफ्रेंस में मेले की सुरक्षा का तो उस वक्त दिवाला ही निकल गया जब एक पत्रकार ने अपने आई.डी. कार्ड पर अपने एक साथी को एन्ट्री करा दी। जबकि एन्ट्री करने वाला व्यक्ति चोरी छिपे नहीं बल्कि भारी पुलिसबल के सामने ही पत्रकार का आई. डी. गले में पहन कर आ जा रहा था। ये अधिकारी मेले की आड़ में सरकारी दामाद बनकर माल चखने में लगे हुए थे। व अपने दोस्तों परिवार वालों की जमकर आवभगत करवा रहे थे। मेला, प्रशासन व पुलिस प्रशासन के लिए कई सवाल छोड़ गया है ।